वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, नहीं। सरकार, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के निवेशकों को शेयरों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोई योजना नहीं बना रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Proposal to Scrap Expenditure tax on Foreign Tourists

100. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to scrap expenditure tax on foreign tourists;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) There is no proposal under Government's consideration to scrap expenditure tax on foreign tourists at present.

(b) In view of the answer at (a) above, it does not arise.

(c) In view of the adjustment in exchange rates the exemption to expenditure incurred, or the payment for which is made, in foreign-exchange, has been withdrawn with effect from the 1st day of October, 1992. Hence, there is no proposal at present under the Government's consideration to scrap expenditure tax on foreign tourists.

चांदी का आयात

101. **डा॰ बापू कालदाते:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार चांदी का आयात करने के लिए उसी प्रकार अनुमति देने पर विचार कर रही है जिस प्रकार उसने सोने का आयात करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो चांदी के आयात के संबंध में सरकार अन्तिम निर्णय कब तक लेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

102. **डा॰ बापू कालदाते:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अपने कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितने कर्मचारियों को बोनस का लाभ प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान वेतन और भत्तों में तो वृद्धि हुई है परंतु बोनस के भुगतान की वेतन-सीमा को बढ़ाया नहीं गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार बोनस के लिए रखी गई वेतन सीमा को समाप्त करके सभी कर्मचारियों को समान बोनस देने का विचार रखती है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे): (क) जी, हां।

(ख) भिन्न-भिन्न बोनस स्कीमों के तहत लाभ पाने वालों की संख्या सम्बंधी सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है।

(ग) बोनस के लिए पात्रता सीमा बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के उपबंधों से सम्बद्ध है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

घरेलू और विदेशी ऋणों की सीमा

103. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू और विदेशी ऋण की सीमा बांधने के प्रश्न पर कोई फैसला लिया है;

(ख) राज्यों को संसाधनों के हस्तान्तरण के संबंध में कौन-कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं; और

(ग) सरकार ने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए क्या उपाय किए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे): (क) सरकारी ऋणों पर सांविधिक अधिकतम सीमा लगाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) राज्यों को संसाधनों का अन्तरण वित्त आयोग की सिफारिशों, योजना आयोग द्वारा यथा-अनुमोदित राज्य योजनाओं के वित्त पोषण की स्कीम और विभिन्न आयोजना-भिन्न और राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रयोजित स्कीमों के संबंध में आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है।

आयोजना-भिन्न अन्तरणों में अल्प बचत संग्रहों और अर्थोपाय अग्रिमों के एवज में ऋण शामिल है। इस संबंध में ब्यौरे वर्ष 1992-93 के व्यय बजट खण्ड—1 और प्राप्ति बजट में उपलब्ध है।

(ग) वर्ष 1992-93 के बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा, जो वर्ष 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 8.5 प्रतिशत से कम करके वर्ष 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.5 प्रतिशत लाया गया था, वित्तीय वर्ष 1992-93 में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 5 प्रतिशत तक और कम लाया जाएगा। यह राजस्व-प्राप्तियों में सुधार करके और व्यय कम करके प्राप्त किया जाएगा।

Cancellation of unutilised loan by World Bank

104. DR. NAUNIHAL SINGH:
SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

Will the Minister of FINANCE be "pleased to state:

(a) whether it is a fact that the World Bank cancelled unutilised loan of $ 1.45 billion for India and cautioned her to expedite the use of the aid;

(b) if so, what are the reasons for which the money could not be utilised;

(c) what are the fields in which the loan amount was to be invested;

(d) what is the reaction of Government thereto;

(e) whether the World Bank has now imposed several new restrictions on the utilisation of loan amount; and

(f) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) to (d) In December 1991 an agreement was arrived at between Government of India and the World Bank to cancel an amount of US $ 1 billion worth of IBRD loans and to redeploy an amount of IDA credit equivalent to US $ 0.65 billion. This arrangement was necessitated by the fact that a large volume of undisbursed loans and credits had-accumulated because of slow project implementation, and substantial devaluation of the rupee in comparison to hard currencies in 1991. In spite of all possible steps being taken to increase the utilisation of aid, the large undrawn balance of IBRD borrowings was slowing down utilisation of aid while making it more difficult to negotiate fresh assistance as the World Bank's maximum exposure limits had nearly been reached in the case of India. Accordingly, after a detailed project-wise analysis of the effects of the rupee devaluation and the actual requirement of rupee resources to meet the committed physical targets, it was decided that the above mentioned amount of US $ 1 billion of IBRD loans, which are available at a relatively higher rate of interest could be cancelled. On the other hand, the IDA credit cf US $ 0.65 billion which is available on very soft terms, was not cancelled but was redeployed for financing a structural adjustment loan as a fast disbursing operation. This latter operation provided substancial balance of payment support during the period of our exceptional financing difficulties.

(c) and (0 The above mentioned operation has not resulted in any new restrictions of loan utilisation.

Steps to control inflation and imports

105. SHRIMATI VEENA VERMA: SHRI SUNIL BASU RAY: SHRI ASHIS SEN: SHRI SUKOMAL SEN: SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: SHRI SHIV PRATAP MISHRA: SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: SHRI RAMDAS AGARWAL: SHRl SURESH KALMADI: SHRI GURUDAS DASGUPTA: SHRI N.E. BALARAM: SHRI RAJNI RANJAN SAHU: SHRI RAM JETHMALANI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the extent to which the recent increase in prices of petrol and